

भारत सरकार  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 766  
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन

766. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का व्यौरा क्या है;
- (ख) देश में राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का व्यौरा क्या है;
- (ग) भारत भर में प्रस्तावित, निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यशील चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थिति क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने मेडिकल पार्क स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा और उनकी स्थिति क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित चिकित्सा उपकरणों के उपयोग और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यकलाप/अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ग), (घ) और (ङ): भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसके लगभग 15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष बीस वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है। भारत सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों

के घरेलू विनिर्माण और स्थिर आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बल प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(i) **चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई एमडी):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 20.03.2020 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का उत्पादन कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है। यह योजना भारत में विनिर्मित और योजना के चार लक्षित खंडों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से चयनित कंपनियों को पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत 32 आवेदकों का चयन किया गया है। 1,356.94 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश में से 1057.47 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है। इस योजना के तहत आवेदकों द्वारा सितंबर, 2024 तक की गई संचयी बिक्री 8039.63 करोड़ रुपये है (जिसमें 3,844.01 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है)।

(ii) **चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना:** पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 20 मार्च, 2020 को "चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन" की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है और कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग को 16 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को इन चार राज्यों में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई। विनिर्मित सामान्य अवसंरचना सुविधा (सीआईएफ) के लिए आवासीय उपकरण संबंधी अधिकतर संरचनाओं के साथ अन्य सभी तीन पार्कों (हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) में सिविल कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है, जबकि उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

चिकित्सा उपकरण पार्क को राज्य सरकार की ओर से निधियन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि लागत में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के लिए विभाग के योजना दिशा-निर्देशों के फ्रेमवर्क के अनुरूप पार्क को लागू करना संभव नहीं था, जबकि विभाग से सभी तरह की सहायता उपलब्ध थी और राज्य को 30 करोड़ रुपये पूर्व में ही जारी किए जा चुके थे। इसलिए, नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है।

(iii) **चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढीकरण के लिए दिनांक 08.11.2024 को नई योजना की शुरुआत**

चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझा बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग का संवर्धन शामिल है, दिनांक 08.11.2024 को 500

करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच उप-योजनाओं के साथ "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना की उप-योजना इस प्रकार है: -

- (i) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएं
- (ii) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना
- (iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास
- (iv) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना
- (v) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना

(ख): योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आधार पर निधि आवंटित नहीं की गई है। "चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत, 2024-25 तक पांच वर्षों में आवंटित निधि 160 करोड़ रुपये हैं और 2023-2024 तक पांच वर्षों में उपयोग की जाने वाली निधि 57.11 करोड़ रुपये हैं। "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" योजना के अंतर्गत आवंटित निधि 22.50 करोड़ रुपये हैं और 22.50 करोड़ रुपये उपयोग किए गए हैं। एमटीजेड, आंध्र प्रदेश सरकार को 2021-2022 तक के लिए आवंटित धनराशि 2024-2025 तक 367 करोड़ रुपये हैं और 2023-2024 तक "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना के अंतर्गत 120 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(च): इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 और इंडिया मेडेटेक एक्सपो 2023 जैसे आयोजनों, कार्यशालाओं और बड़े आयोजनों के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। औषध विभाग द्वारा इंडिया मेडेटेक एक्सपो 2023 का आयोजन दिनांक 17-19 अगस्त 2023 तक हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात में "भारत: अगला मेडेटेक ग्लोबल हब - डिजिटल, डायग्नोस्टिक्स और उपकरणों का भविष्य" थीम के साथ किया गया था। एक्सपो में स्टार्ट-अप, एमएसएमई, बड़े उद्योग, अस्पताल, सरकारी एजेंसियां, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और शिक्षा जगत सहित चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारक एक साथ आए। इस कार्यक्रम ने भारत की चिकित्सा उपकरण क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया और घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा दिया। एक्सपो में कुल 225 कंपनियों ने भाग लिया, जो चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक्स, इमेजिंग, होम मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक डिवाइस, प्रयोगशाला उपकरण आदि जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। 50 देशों से कुल 217 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने एक्सपो का दौरा किया। 225 प्रदर्शकों द्वारा 3-दिवसीय कार्यक्रम में कुल 4909 व्यावसायिक बैठकें आयोजित की गईं।

विभाग की नई उप-योजना - चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना का उद्देश्य अध्ययन और सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे कार्यकलापों का समर्थन करके भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है।

\*\*\*\*\*